



विपक्ष का निर्वाचन आयोग तक मार्च रोका गया...8 घंटे के धरने के बाद राहुल-प्रियंका हिरासत में...

राहुल बोले-देश के साथ जो हुआ वह देशद्रोह



नई दिल्ली,06 अक्टूबर 2026। 'बोट चोरों' के आरोपों को लेकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्षी नेताओं एवं सांसदों का मंगलवार को संसद से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक मार्च पुलिस ने रोक दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के साथ जो किया गया है वह देशद्रोह है। सभी की जांच होगी। मार्च में बीजू जनता दल समेत लोकसभा और राज्यसभा के 300 से अधिक विपक्षी सांसद शामिल थे। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद राहुल गांधी,प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग मुख्यालय से सटे आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दिया। राहुल गांधी ने यहां पत्रकारों से कहा कि विपक्षी सांसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलने जा रहे थे,लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। देश की आवाज का

दिल्ली पुलिस बोली...राहुल ने मार्च निकालने कोई परमिशन नहीं ली...

दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि इंडिया ब्लॉक के नेता,6 अक्टूबर को सुबह करीब 10:30 बजे संसद भवन से निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च निकालेंगे। इसके लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था,इसलिए हमारी तरफ से कोई परमिशन जारी नहीं की गई थी। इस जमावड़े को बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के उल्लंघन की आशंका के चलते सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने बार-बार घोषणा कर प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक वापस जाने की अपील की गई। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया और वहां बने रहे। 260 व्यक्तियों, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं, को हिरासत में लेकर दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों में ले जाया गया, जहां उनके संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 300 सांसदों को निर्वाचन आयुक्तों से मिलने से वयो रोका गया। जब सांसद निर्वाचन आयोग के कार्यालय से महज 50 गज की दूरी पर हैं और फिर भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा,तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को



राहुल ने बैरिकेड पर चढ़कर तिरंगा फहराया

पुलिस ने संसद मार्ग पर नीति आयोग और आकाशवाणी भवन के बीच भारी बैरिकेड लगाए थे। इस बीच मार्च रोके जाने के बाद राहुल गांधी सड़क पर धरने पर बैठ गए, फिर अचानक एक बैरिकेड पर चढ़ गए और तिरंगा लहराया। कई युवा सांसद भी उनके पीछे-पीछे गए। इस बीच, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ज्ञानेश, हो गया भाई... अब इस्तीफा देने का समय आ गया है।' विपक्ष के नेताओं ने भी सोर्सरी के खिलाफ नारे लगाए, जैसे 'बोट चोर, गद्दी छोड़ो।'

ज्ञानेश कुमार की मां बोली-राहलों ने घर गंद किछ गंगजल छिड़कर अमृत में कांछीचिन्ने ने दीक्षार पर 'बोट चोर' लिखा था

आगरा में मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर का शुद्धिकरण किया गया। ज्ञानेश कुमार की 76 वर्षीय मां सत्यवती ने कहा, '28 सितंबर को कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग घर के बाहर आए थे। उन्होंने घर को गंदा किया था। अब घर को शुद्ध किया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि यह धार्मिक आयोजन है। इसे शांतिपूर्वक और शांति के लिए किया जा रहा है। घर के बाहर अखिल भारतीय माधुर देश महासभा की महिलाएं जुटीं। सभी ने पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के घर पहुंचकर गंगाजल का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया गया। अब सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार का पैतृक घर आगरा के विजय नगर में है। 28 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर के बाहर प्रदर्शन किया था।

खड़गे बोले-लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं



मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह आंदोलन देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के अधिकारों से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए लोगों के अधिकार छीन रही है और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। खड़गे ने कहा कि जिस तरह

से सत्ता हासिल की गई,वह उचित नहीं था और इसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर देश में नौ राज्यों की विधानसभाएं भंग की जा सकती हैं,तो यहाँ की अवैध व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेगी।

राहुल 'ज्ञानेश,इट्स डन ब्रो' का पोस्टर लेकर पहुंचे...

राहुल Gen-Z से कनेक्ट के लिए प्रदर्शन में 'ज्ञानेश,इट्स डन ब्रो'का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद इस वर्ग को सीधे मैसेज देना था। देश में आज हर चौथा वोटर जेन-जी है। चुनाव आयोग के मुताबिक, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देश के कुल मतदाताओं में 18-29 साल के वोटर्स की हिस्सेदारी 22.78% थी।

अखिलेश बोले...ज्ञानेश कुमार निषध है तो हमारी बात सुनें...

अखिलेश यादव ने कहा- अगर ज्ञानेश कुमार निषध है तो उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए। यह लोकतंत्र बचाने की बात है। पुलिस को बच्चों के साथ और प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।

शिवराज सिंह बोले...यह जनादेश का अपमान है...

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह जनादेश का अपमान है। यह लोकतंत्र की चिंता नहीं,हर की खीझ है। विपक्ष जनादेश का अपमान कर रहा है।



भारतीय नौसेना के लिए 661 करोड़ रुपये से खरीदे जाएंगे ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम



नई दिल्ली,06 अक्टूबर 2026। भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर खरीदे जाएंगे,जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (बीएपीएल) के साथ 661 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। यह खरीद (इंडियन-इंडोईरोएम) कैटेगरी के तहत की जाएगी। इस समझौते पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 68 फीसदी स्वदेशी कंटेंट के साथ यह प्रोजेक्ट लघु उद्योगों समेत अलग-अलग भारतीय इंडस्ट्रीज की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह प्रोजेक्ट तीन साल में रोजगार पैदा करेगा। यह भारत के समुद्री सुरक्षा आकृतिक्कर और रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत करेगा और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी को स्वदेशी बनाने की चाल रही कोशिशों में एक अहम पड़ाव है। अलग-अलग फ्रंटलाइन वॉरशिप पर लगा ब्रह्मोस सिस्टम समुद्री हमले के ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना का मुख्य सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। यह वैपन सिस्टम सुपरसोनिक स्पीड से बहुत दूर से जमीन और समुद्र के टारगेट पर एकदम सही निशाना लगा सकता है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी बूस्टर के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया है, जो भारत की आत्मनिर्भरता के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इस ब्रह्मोस मिसाइल में नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम के तहत किया जा रहा है। इस संयुक्त उद्यम में डीआरडीओ भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। नौसेना अपने वॉरशिप आईएनएस विशाखापत्तनम,गाइडड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगाओ,युद्धपोत आईएनएस दिल्ली,आईएनएस रणविजय,स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से समय-समय पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर चुकी है।

कैबिनेट : छोटे एवं मंजोले उद्यमों को आसानी से पूंजी के लिए विकास कोष बनाएगी सरकार

नई दिल्ली,06 अक्टूबर 2026। केंद्र सरकार 'लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष' (एसजीएफ) बनाएगी। इसे सरकार विभिन्न निवेश कोषों के माध्यम से 10 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। इससे छोटे एवं मंजोले उद्यमों को आसानी से पूंजी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत सरकार की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि मौजूदा इक्विटी सहायता का अधिकांश हिस्सा प्रारंभिक चरण और सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किया जाता है। इस कोष का उद्देश्य व्यवहार्य लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विकास-पूंजी अंतर को पाटना है। यह कोष टियर-टू और टियर-थ्री औद्योगिक समूहों में विनिर्माण से जुड़े लघु एवं मध्यम उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कोष उद्यमों को विस्तार करने, प्रौद्योगिकी अपनाने और वैश्विक बाजारों में प्रवेश पाने में सहायक करेगा। एसजीएफ से विस्तार, उत्पादकता और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि यह केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई उन समग्र घोषणाओं का हिस्सा था। इन घोषणाओं का उद्देश्य समग्र रूप से एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समानता, मुद्रा सुलभता और पेशेवर सहायता प्रदान करना था।

बंगाल उपचुनाव : नंदीग्राम में 79.39 और रेजीनगर में 78.42 फीसदी मतदान,विधायक हुमायूं कबीर गिरफ्तार

कोलकाता,06 अक्टूबर 2026। पश्चिम बंगाल के दो बेहद चर्चित और संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद के रेजीनगर, में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपचुनाव संपन्न हुआ। चुनाव आयोग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार,मतदान प्रतिशत काफी ऊंचा रहा। नंदीग्राम में 79.39 प्रतिशत और रेजीनगर में 78.42 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कड़ी सुरक्षा के बावजूद दोनों क्षेत्रों से राजनीतिक तनाव,पुलिस के साथ झड़प और विपक्षी दलों द्वारा मतदान में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। सबसे बड़ी घटना मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में घटी, जहां पुलिस से तीखी बहस के बाद आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के प्रमुख नानोदा से विधायक हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया।



रेजीनगर में मतदान के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब विधायक हुमायूं कबीर की अपनी पार्टी के कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस हुई। कबीर ने पुलिस पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इशारे पर काम करने और मतदाताओं को डराने का गंभीर आरोप

लगाया था। उन्होंने कथित तौर पर लोगों से पुलिस की ज्यादातियों का डंडों से विरोध करने का भी आह्वान किया था। वायरल हुए घटना के दृश्यों में पुलिसकर्मियों को कबीर को शर्ट से पकड़कर गाड़ी में बिठाते हुए देखा गया। मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सचिन मकड़ ने स्पष्ट किया कि

तमिलनाडु के धारापुरम में मतदान अधिकारी को हटाया गया...

तमिलनाडु के धारापुरम विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को एक मतदान अधिकारी को झुठरी से हटा दिया गया। उस पर आरोप है कि उसने एक बुजुर्ग महिला मतदाता से 'सीटी' चुनाव चिह्न वाले उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा। इसके बाद मतदान केंद्र पर हंगामा हो गया। डीएमके और एआईएडीएमके समेत विपक्षी दलों के मतदाता एजेंटों ने अधिकारी का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम कर रहा था। विरोध के बाद मतदान केंद्र पर कुछ घंटों के लिए मतदान प्रभावित रहा। बाद में संबंधित मतदान अधिकारी को वहां से हटाकर उसकी जगह दूसरे अधिकारी को तैनात किया गया।

कबीर न तो उम्मीदवार थे और न ही अधिकृत चुनाव एजेंट, इसलिए उनका मतदान केंद्रों के आसपास घूमना नियमों का उल्लंघन था। कबीर पर मतदाताओं को प्रभावित करने और भड़काने का आरोप है। इस घटना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहित काफी ने रेजीनगर थाने के बाहर धरना दिया और पुलिस पर

पक्षपात का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द कर दोबारा मतदान कराने की मांग की। वाम दलों (सीपीआई-एम) ने भी मोरारीजी क्षेत्र के दादपुर में बूथ संख्या 112, 113, 114 और 122 पर अपने एजेंटों को रोकें जाने और मतदाताओं की उंगलियों पर स्याही लगाकर उन्हें वापस भेजने का आरोप लगाया।

सड़क पर खड़े ट्रेलर में घुसी कार,7 की मौत

तेज टक्कर से ट्रेलर के पहिए टूटकर अलग हो गए,मुक्तक का मामला

भावनगर,06 अक्टूबर 2026। गुजरात के भावनगर-सोमाना नेशनल हाइवे पर मंगलवार को भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा शिव शक्ति होटल के पास हुआ,जहां तेज रफ्तार बोलेरो एसयूवी सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे जा टकराई। बोलेरो में अलग शिपयार्ड के 7 कर्मचारी सवार थे। सभी काम के सिलसिले में भावनगर से अलग शिपयार्ड जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि भारी-भरकम ट्रेलर तक के अंगले पहिए टूटकर अलग हो गए थे।

हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी,जबकि एक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान विजयभाई चंदुभाई वोरा, पोचूषभाई बिपिनचंद्र शाह,प्रितेशभाई बिपिनचंद्र भवाणी, भार्गवभाई गोसाई,हिरनभाई मेहता और योगेशभाई शाह और जयेशभाई हिमन्तभाई वसानी के रूप में हुई है।

रक्षा मंत्री ने विशाखापट्टनम में लॉन्च किया पहला पलीट सपोर्ट शिप 'सूर्या'



नई दिल्ली,06 अक्टूबर 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में पहला पलीट सपोर्ट शिप 'सूर्या' लॉन्च किया। इसके अलावा दूसरे पलीट सपोर्ट शिप एफएसएस-5 की कोल रखी और अपग्रेडेड स्लिपवे-4 एवं 300 टन के गोलियथ क्रेन का उद्घाटन किया। ये भारत की स्वदेशी शिपबिल्डिंग क्षमता मजबूत करने और भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल पहुँच एवं सहनशीलता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री ने विशाखापट्टनम को बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने का आह्वान किया और भारतीय शिपयार्ड से आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा

की ओर बढ़ने का आग्रह किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इन तीनों माइलस्टोन का महत्व अलग-अलग उपलब्धियों से कहीं ज्यादा है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड न केवल अपनी जहाज बनाने की क्षमता को मजबूत कर रहा है, बल्कि भारत की समुद्री ताकत की नींव भी मजबूत कर रहा है। उन्होंने 1948 में विशाखापट्टनम में आजाद भारत में बने पहले जहाज 'जला उषा' की लांचिंग को याद करते हुए भारत की पुरानी समुद्री विरासत पर जोर देते हुए कहा कि देश का समुद्र से रिश्ता बहुत पुराने समय से है। उन्होंने आठ दशकों से ज्यादा समय से देश की समुद्री और रक्षा जरूरतों में इसके योगदान की तारीफ की।

संपादकीय

एशियाई खेलों में भारत

हम संतोष कर सकते हैं कि एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस प्रतिष्ठित खेल स्पर्धों में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 85 पदक जीते। जिसमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। आइची-नागोया में संपन्न एशियाई खेलों के आखिरी दिनों में भारतीय खिलाड़ियों ने दमखम दिखा कर सोने के तमगों की संख्या बढ़ाई है। निस्संदेह,कह सकते हैं कि हम एशिया में पहले चार देशों में शुमार हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि भले ही हम चौथे स्थान पर रहे हैं,लेकिन इन खेलों में नंबर एक व दो रहे चीन व जापान के आगे हम कहाँ खड़े हैं? इस बार भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने यह भी सोचने को मजबूर किया कि आने वाले कुछ दशकों में भारत ओलंपिक की दावेदारी में कहाँ उठरता है? वैसे इस बार के एशियाई खेलों से जुड़ी कुछ सुखद स्मृतियां भी हैं, मसलन तीरंदाजी में हमने नौ मेडल जीते हैं। जिसमें पांच स्वर्ण पदक शामिल हैं। सुखद यह भी है कि कुमकुम मोहोद रिक्वं कैटेगरी में भारत की पहली व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी बनीं। भारतीय खिलाड़ियों को बॉक्सिंग और रसलिंग में क्रमशः तीन और दो स्वर्ण पदक मिले। वहीं दूसरी ओर प्रणवी उसं एशियाई खेलों में व्यक्तिगत गोल्फ गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। वहीं दूसरी ओर इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट,हॉकी और कबड्डी में अपना वर्चस्व कायम रखा।

महिला हॉकी में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि बहुत खास रही। उन्होंने अनुशासन और ऊंचे मनोबल के साथ बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मौजूदा चैंपियन चीन को हराकर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक का 44 साल का हमारा इंतजार खत्म किया। लेकिन हमारे खिलाड़ी एथलेटिक्स में हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। एकमात्र स्वर्ण महिलाओं की 4×400 मीटर रिले रेस में हासिल हुआ। निशानेबाजों का प्रदर्शन भी उत्साह जगाने वाला नहीं रहा। इस बार हमें,पिछले ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ने निराश किया। वह इस बार खाली हाथ लौटी हैं। वैसे पिछली बार चीन में हुए एशियाई खेलों से तुलना करें तो इस बार हमारा प्रदर्शन फीका रहा। तब हमने 28 स्वर्ण पदकों के साथ 106 मेडल जीते थे। इस बार सात स्वर्ण समेत कुल 21 पदकों की कमी, हमारे खेल नीति-निर्याताओं के लिये एक चेतावनी जैसी है। हालांकि, यह वक़्त हमारे लिये नागोया में प्ली काामयाबियों का जश्न मनाने का है। लेकिन हमें अपनी कमजोरियों को लेकर भी आत्ममथन करने की जरूरत है। नि:संदेह,भारत में खेलों का भविष्य चंद खिलाड़ियों की कामयाबी से तय नहीं किया जा सकता है। हमें एशियाड के बाद ओलंपिक के लिये युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी होंगी। इस कामयाबी के लिये नई प्रतिभाओं की पहचान,विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, मानसिक रूप से सशक्त खिलाड़ी तैयार करने तथा विश्वस्तरीय स्पोर्ट सिस्टम बनाने की जरूरत होगी।

झील के आंसू

रात के ठीक तीन बजकर बयालीस मिनट पर कमांड सेंटर की विशाल स्क्रीन पर अचानक खतरे का एक लाल गोला धड़कने लगा। अल्ट्राधुनिक टेलीस्टार रडार ने शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली झील के मुहाने पर एक बड़े अवैध कब्जे को चिन्हित किया था। पलक झपकते ही मिशन ब्लू वॉटर सक्रिय हो गया और सायरन बजाती वल्रडरबंद गाड़ियां,आसमान में मंडराता नाइट विजन ड्रोन और दहशूदा हुआ पीला बुलडोजर दलदली पगडंडी पर दौड़ पड़े। अफसरों के वायरलेस पर गुंजते रहस्यमयी कोड और बूटों की भारी आवाजें ऐसा खोफ पैदा कर रही थीं मानो किसी खूबार अंतरराष्ट्रीय माफिया का किला ध्वस्त करने की तैयारी हो। भारी कोहरे को चीरते हुए जैसे ही बुलडोजर का विशाल पंजा हवा में तना, हर सिपाही की बंदूक का रख उस रहस्यमयी ठिकाने की तरफ मुड़ गया जहां से किसी भयानक प्रतिरोध के फूटने का अंदेश था। दहशत के उस सन्नाटे को चीरते हुए जब जंग लगा लोहे का दवाजा खुला,तो अंदर से कोई हथियारबंद माफिया नहीं बल्कि सत्तर साल का लाचार दर्जी मस्तान बाहर निकला। उसके पीछे सहमी खड़ी थी नौ साल की अनाथ पोती जोया,जिसने फटे हुए बस्ते को अपनी छाती से ऐसे चिपका रखा था जैसे वही उसकी हूण हो। मस्तान ने थरथरते हाथों से चालीस साल पुरानी स्टॉप ड्यूटी और म्युनिसिपल टैक्स की रसीदें अफसरों के कदमों में बिछ दीं। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि साहब, यह खून पसीने की कमाई से बना आशियाना है, इसे बख्शा दीजिए। मगर डिजिटल तकनीक से लैस अफसर ने उन मटरेबंद कागजों को हाथ तक नहीं लगाया। अफसर ने अपने टैबलेट की नीली चमक मस्तान की पथराई आँखों पर चमकाते हुए बेहद सपाट लहजे में फैसला सुना दिया कि आधुनिक पर्यावरण नियमों के मुताबिक यह संवेदनशील बर्फ जोन है और प्रकृति के संतुलन की खातिर इस जलस्रोत को तत्काल खाली कराना हमारी संवैधानिक मजबूरी है।

इस मुल्क में अंधा कानून अक्सर सिर्फ सबसे कमजोर इंसान की छाती पर टिककर ही अपनी आंखों की रोशनी साबित करता है। मस्तान ने रोते हुए अपनी कांपती उंगली ठीक पचास मीटर दूर झील के सीने के बीचोंबीच उठाई,जहां पचास मंजिला आलीशान शीशे का टावर पानी में अपनी कंक्रीट की जड़ें जमाए शान से खड़ा था। उस गगनचुंबी इमारत के रूफटॉप रिविंग पूल की नीली बतियां झील की काली लहरों पर तैर रही थीं और उस पर चमकता विशाल बोर्ड पर्यावरण अनुकूल स्वर्ग का इशतिहार बेच रहा था। मस्तान ने रंधे गले से सवाल दागा कि क्या झील के दिल को चीरकर खड़ा यह पचास मंजिला शीशमहल बफर जोन नहीं तोड़ता,क्या इससे जलस्रोत नहीं मरता। अफसर ने बेहद संजीदगी और दार्शनिक मुस्कान के साथ चरमा ठीक करते हुए जवाब दिया कि कानून आंसुओं पर नहीं बल्कि नेशनल ट्रिब्यूनल के विलयर्स, डिजिटल मंजूरी और अदालत के स्टे आर्डर पर चलता है। यह इस निष्ठुर व्यवस्था का सबसे घिनौना फलसफा था,जहां पूंजीपतियों का महाविनाश विकास बन जाता है और एक गरीब की टूटी छत पारिस्थितिकी का सबसे बड़ा खतरा करार दी जाती है। बुलडोजर के भारी पहिर घूमे और उसके लोहे के पंजे ने पूरी कृता से उस मिट्टी और टीन की झोपड़ी पर प्रहार कर दिया। एक चीखती हुई आवाज के साथ मस्तान की पुरानी सिलाई मशीन,जोया की स्कूल की कापियां और मिट्टी की एक छोटी गुल्लक मलबे में तब्दील हो गई। गुल्लक के टूटने से छिटेके चंद सिक्के दलदल के काले कीचड़ में हमेशा के लिए डगल हो गए। अफसर ने एक पल की भी देर किए बिना स्क्रीन पर उंगली चलाई और व्यवस्था की पीठ थपथपाते हुए फाइल बंद कर दी कि शून्य दशमलव शून्य शून्य एक हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर पर्यावरण की रक्षा का ऐतिहासिक कर्तव्य पूरा कर लिया गया है। काम खत्म होते ही सुरक्षाबलों का भारी काफिला धूल का गुबार उड़ता हुआ शहर की चकाचौंध की तरफ लौट गया,मनो उन्होंने प्रकृति को विनाश के बनुत बड़े संकट से बचा लिया हो। चारों तरफ पसरे मखमली सन्नाटे में बूझ मस्तान घुटनों के बल बैठकर मलबे से अपनी पोती का भीगा हुआ बस्ता तलाशने लगा।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

—सम्पादक



अजय कुमार लखनऊ (उ. प्र.)

भारतीय राजनीति के फलक पर विपक्ष इस समय पूरी तरह से आक्रामक और सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। राफेल डील से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग और स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईर) जैसे मुद्दों पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छेड़ रखा है। इस आक्रामक घेरेबंदी के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का वह पारंपरिक काउंटर अटैक दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शह की जोड़ी जानी जाती है। जबकि विपक्ष लगातार मुद्दे बदल कर हमलावर है। विपक्ष का एजेंडा और रणनीति लगातार बदल रही है। कुछ समय पहले तक जो विपक्ष सिर्फ संसद के भीतर विरोध दर्ज कराता था, वह अब अदालतों, स्वतंत्र मंचों और अंतरराष्ट्रीय कड़ियों को जोड़कर

सरकार को घेर रहा है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से मोर्चा खोला है,उसने सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने का काम किया है। 06 अक्टूबर को भी इंडी गठबंधन ने सीईसी के खिलाफ सड़क पर खूब संग्राम किया,जवाब में भाजपा के बड़े नेता जैसे कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान या पार्टी प्रवक्ता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के इस अभियान को भ्रामक और अराजकता फैलाने वाला करार देने तक ही सीमित नजर आयेें। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका सांगठनिक ढांचा और जमीनी कार्यकर्ता माने जाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर के इस राजनीतिक हो-हल्ले में भाजपा के पार्षद,विधायक और सांसद जैसे जनप्रतिनिधि अपने नेतृत्व के पक्ष में मुखरता से खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। संसद और मीडिया में गिने-चुने प्रवक्ताओं को छोड़ दें,तो जमीन पर सांसदों और विधायकों का कोई बड़ा समूह विपक्ष के इन तथाकथित फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए जनता के बीच जाता नहीं दिख रहा है। चाहे वह परीक्षाओं की प्रणाली को लेकर विपक्ष का पेरार हो या फिर चुनाव सुधारों पर फैलाया जा रहा भ्रम, भाजपा के स्थानीय नेता अपनी ही सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बचाव करने में हिचकिचाते नजर आ रहे हैं। इस खामोशी ने जनता के एक बड़े वर्ग में यह संदेश दिया है कि विपक्ष के आरोपों का ठोस जवाब देने में पार्टी का जमीनी केडर अवमर्थ महसूस कर रहा है,जबकि विपक्ष अब केवल राजनीतिक रलियों तक सीमित नहीं है,उसने अदालतों को अपना मुख्य

रणनीतिक केंद्र बना लिया है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से लेकर सरकार की प्रशासनिक नीतियों तक,हर संवेदनशील मुद्दे को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भाजपा के कानूनी सलाहकारों और कानूनिविदों की टीम मीडिया या सार्वजनिक फोरम पर उस तर्किकता और आक्रामकता के साथ खड़ी नहीं दिखती, जिसकी जरूरत है। अदालती फैसलों या चल रही बहसों का सरलीकृत रूप जनता के सामने रखने में भाजपा का कानूनी विंग पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रहा है। जब विपक्ष के वकील अदालतों के बाहर मीडिया कैमरों के सामने एकतरफा नैरेटिव सेट कर रहे होते हैं, तब भाजपा की तरफ से उस कानूनी बारीकी को जनता की भाषा में समझाने वाला कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता।

भाजपा का मीडिया सेल केवल रोजमर्रा की तू-तू मैं-मैं में उलझा हुआ है, जिससे वह धार गायब हो चुकी है जो कभी विरोधियों के नैरेटिव को चंद घंटों में जमींदोज कर देती थी। राजनीतिक पडिटों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शह की जोड़ी हमेशा अत्युत्पाित और विनाशकारी काउंटर-अटैक के लिए जानी जाती रही है। रक्षा मंत्री राजनथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुरासन के जरिए विपक्ष के झूठे नैरेटिव को बेअसर किया है, लेकिन संगठन के स्तर पर यह असर फीका पड़ रहा है।

उपर,मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने में विदेशी शक्तियों और बाहरी तत्वों के शामिल होने के आरोपों पर भी भारतीय राजनीति में तीखी बहस जारी है। सत्ता पक्ष और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि भारत



की संप्रभुता,लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सरकार की छवि को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि,विपक्ष इन दावों को घेरलू विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक जरिया बताता है। विदेशी जमीन से संचालित डिजिटल इकोसिस्टम पर सत्तारूढ़ दल भाजपा ने आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया है कि देश के भीतर सरकार विरोधी एजेंडा और वोट चोरी जैसे नैरेटिव को हवा देने वाले कई सोशल मीडिया हैंडल भारत से नहीं,बल्कि विदेशी धरती से संचालित हो रहे हैं। भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा सार्वजनिक किए गए विवरणों के अनुसार,कांग्रेस और उसके सहयोगी तंत्र से जुड़े कुछ प्रमुख सोशल मीडिया हैंडल और इन्फ्लुएंसर्स के नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और थाईलैंड जैसी विदेशी लोकेशंस से जुड़े पाए गए हैं। पार्टी का दावा है कि यह भारत में असंतोष भड़काने के लिए एक व्यवस्थित विदेशी

नेटवर्क का हिस्सा है।भारत में बड़े आंदोलनों (जैसे छात्र प्रदर्शन या किसान आंदोलन) के दौरान विदेशी टूलकिट की सक्रियता के प्रमाण मिले हैं। सुरक्षा बलों और साइबर सेल की जांच रिपोर्टों के अनुसार, हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तान स्थित हैंडलों से संचालित होने वाले फेक न्यूज टूलकिट्स सक्रिय गए गए हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा जनित और हेरफेर किए गए वीडियो का उपयोग कर युवाओं को सरकार और रक्षा बलों के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया गया। इससे पहले, ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में भी खालिस्तानी संगठनों और विदेशी कड़ियों (जैसे कनाडा स्थित पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन) के शामिल होने के आरोप लगे थे। भाजपा के आईटी सेल ने इसे रेखांकित करते हुए आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें भारत में एक कमजोर गठबंधन सरकार स्थापित करने के लिए वित्तीय और रणनीतिक प्रयास कर रही थीं।

बदलाव का इंतजार..बालिकाएं स्त्रियां अभी भी अपेक्षित अधिकार से वंचित

समय बदला,तकनीक बदली,जीवन-शैली बदली,बाजार बदला और फैशन भी बदल गया। महिलाओं को उपभोक्तावादी संस्कृति ने विलासों और प्रदर्शन की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने के नए-नए तरीके खोज लिए। किंतु दु:ख प्रश्न यह है कि क्या समाज की मूलभूत सोच बदली? क्या बालिका शिक्षा शत-प्रतिशत हो गई? क्या देहेज प्रथा समाप्त हो गई? क्या स्त्री उपीड़न इतिहास बन गया? दुर्भाग्य से इन प्रश्नों का उत्तर अभी भी नकारात्मक है। अनेक समस्याएँ आज भी यथावत बनी हुई हैं, बल्कि कई मामलों में उन्होंने और अधिक विकराल रूप धारण कर लिया है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी अपेक्षित सम्मान और अवसरों से काफी दूर दिखाई देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य,सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में सुधार तो हुआ है, किंतु वह इतना व्यापक नहीं है कि समाज को संतोष हो सके। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि शिक्षा का प्रसार होगा तो समाज की कुरीतियाँ स्वतः समाप्त हो जाएँगी। सिरियाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी और बेटी को बोझ नहीं, अवसर माना जाएगा। कुछ क्षेत्रों में प्रगति अवश्य हुई है,किंतु धरातल पर तस्वीर अभी भी अधूरी है।



संजीव ठाकुर, रायपुर छातीसगढ़

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर लगभग 46.4 प्रतिशत तक पहुँचा है,जो पहले 41 प्रतिशत था। यह सुधार उत्साहजनक है,किंतु इसका अर्थ यह भी है कि आधी से अधिक महिलाएँ अभी भी दस वर्ष की बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या आज भी चिंता का विषय बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में असमानता का एक कारण बाल विवाह,गरीबी,सामाजिक रुढ़ियाँ तथा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी हैं। अनेक परिवार आज भी पुत्र की शिक्षा को निवेश और पुत्री की शिक्षा को व्यय मानते हैं। यही सोच आगे चलकर देहेज जैसी कुप्रथा को जन्म देती और इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि शिक्षा और आधुनिकता के दावों के बीच देहेज का दानव आज भी जीवित है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत 15,489 मामले दर्ज किए गए तथा देहेज से संबंधित घटनाओं में 6,156 महिलाओं की मृत्यु हुई। अर्थात प्रतिदिन लगभग 17 महिलाओं ने देहेज की कीमत अपने जीवन से चुकाई। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की व्यापक तस्वीर भी चिंता उत्पन्न करती है। वर्ष 2023 में देशभर में महिलाओं के विरुद्ध लगभग 4.48 लाख अपराध दर्ज किए गए। इनमें सबसे बड़ी संख्या पति अथवा रिश्तेदारों द्वारा कूटा के मामलों की रही, जो कुल अपराधों का लगभग 30 प्रतिशत है। यह स्थिति केवल आँकड़ों की कहानी नहीं है; यह उन लाखों बेटीयों, बहनों और

माताओं की पीड़ा का दस्तावेज है जो आज भी भेदभाव,हिंसा और असमानता का सामना कर रही हैं। समाज सुधारिका सावित्रीबाई फुले ने कहा था यदि तुम शिक्षित हो जाओगे तो तुन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होगा।

वहीं डॉ. भीमराव आंबेडकर का प्रसिद्ध कथन है कि किसी समाज की प्रगति का आकलन उसकी महिलाओं की प्रगति से किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है,किंतु यदि आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जिस राष्ट्र ने अपनी महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा,वह कभी महान नहीं बन सकता। क्योंकि केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है,आवश्यक यह है कि बालिका शिक्षा को सामाजिक सम्मान,आर्थिक सुरक्षा और समान अवसरों से जोड़ा जाए। जब तक बेटी को परिवार की उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा,जब तक विवाह को आर्थिक लेन-देन का माध्यम समझा जाएगा,तब तक देहेज की मानसिकता समाप्त नहीं होगी। विडंबना यह है कि एक ओर हम महिला सशक्तिकरण के नारे लगाते हैं,बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं,बेटी बच्चाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं,किंतु बड़े सपने देखने से हिचकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ी उपलब्धियाँ पर गर्व करते हैं, दूसरी ओर कन्या के जन्म पर चिंता और विवाह के समय देहेज की चर्चा अभी भी अनेक घरों में सामान्य बात मानी जाती है। यह दोहरा सामाजिक चरित्र हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।

आईआईटी से आगे : महान वैज्ञानिकों की ग्रामीण जड़ें

विद्यार्थी मशीनों की कार्यप्रणाली समझने की स्वाभाविक प्रवृति विकसित कर सकता है। वैज्ञानिक सोच अवसर डिग्री से नहीं,बल्कि एक प्रश्न से शुरू होती है। इतिहास भी बताता है कि वैज्ञानिक प्र प्रिभा केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों तक सीमित नहीं है। भारत के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने साधारण परिस्थितियों से अपनी यात्रा शुरू की और अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपनी पहचान बनाई। सर सी. वी. रमन, भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता, ने आईआईटी से अपनी वैज्ञानिक यात्रा शुरू नहीं की थी। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनका कार्य प्रसिद्ध रमन प्रभाव के रूप में जाना गया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि मौलिक वैज्ञानिक सोच केवल प्रतिष्ठित संस्थानों की चारदीवारी तक सीमित नहीं होती। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,जिन्हें लोकप्रिय रूप से भारत के ‘मिसाइल मैन’ के रूप में याद किया जाता है, रामेश्वरम के एक साधारण परिवार से आए थे। एक छोटे से तटीय शहर से भारत के सर्वोच्च सवैधासिक पद तक उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि शिक्षा,दृढ़ संकल्प और सपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ऐसे अनेक वैज्ञानिकों,इंजीनियरों,गणितज्ञों, चिकित्सकों और आविष्कारकों की कहानियाँ हैं,जिनका प्रारंभिक जीवन किसी बड़े या विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान से बहुत दूर था। इसका अर्थ यह नहीं है कि आईआईटी या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान आवश्यक नहीं हैं। इसके विपरीत,वे उच्च शिक्षा,अनुसंधान सुविधाओं और बौद्धिक वातावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तविक संदेश यह है कि प्रतिभा किसी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले ही मौजूद होती है। एक प्रतिष्ठित संस्थान प्रतिभा को निखार सकता है, लेकिन वह जिज्ञासा को शून्य से पैदा नहीं कर सकता। यह बात

विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। गाँवों में लाखों बच्चे असाधारण प्रतिभा रखते हैं, लेकिन उनमें से अनेक को उचित मार्गदर्शन,संसाधन और आत्मविश्वास नहीं मिल पाता। कुछ विद्यार्थी इसलिए बड़े सपने देखने से हिचकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ी उपलब्धियाँ केवल शहरों या प्रतिष्ठित स्कूलों के बच्चों के लिए हैं। इस सोच को बदलना होगा।

सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए— ‘मैं क्यों नहीं?’ ‘इस आत्मविश्वास को पैदा करने में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा नहीं करता। वह विद्यार्थियों को निरीक्षण करने,प्रश्न पूछने,प्रयोग करने और स्थापित धारणाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। अत्याधुनिक प्रयोगशाला के बिना भी शिक्षक दैनिक जीवन को वस्तुओं से विज्ञान की सरल गतिविधियाँ करवा सकते हैं। एक गिलास पानी, चुंबक,पता,छाया,साइकिल का पहिया या गाँव का तालाब—इनमें से कोई भी वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल की शुरुआत बन सकता है। माता-पिता को भी समझना होगा कि महंगे संसाधन उपयोगी हो सकते हैं,लेकिन बौद्धिक विकास का एकमात्र आधार नहीं है। बच्चों को किताबें,प्रोत्साहन,सोचने का समय और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता चाहिए। हमें हमेशा यह पूछने के बजाय कि ‘तुम्हारे कितने अंक आए?’ ,कभी-कभी यह भी पूछना चाहिए— ‘आज तुमने क्या नया खोजा या सीखा?’ यदि स्कूल, शिक्षक, पुस्तकालय और समुदाय मिलकर काम करें,तो भारत के गाँव वैज्ञानिक जिज्ञासा के शक्तिशाली केंद्र बन सकते हैं। डिजिटल तकनीक ने इस संभावना को और बढ़ा दिया है। आज किसी दूरदराज के गाँव में बैठा विद्यार्थी दुनिया के प्रमुख

विश्वविद्यालयों के व्याख्यान देख सकता है,डिजिटल पुस्तकें पढ़ सकता है,वैज्ञानिक सिमुलेशन का अध्ययन कर सकता है और दुनिया में हो रहे नए शोध एवं आविष्कारों के बारे में जान सकता है। गाँव की कक्षा और विश्व की आधुनिक प्रयोगशाला के बीच की भौगोलिक दूरी अब तेजी से कम हो रही है। लेकिन केवल जानकारी तक पहुँच पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को ऐसे मार्गदर्शकों की आवश्यकता है,जो उन्हें सही और विश्वसनीय ज्ञान तथा गलत सूचना के बीच अंतर समझा सकें। उन्हें अपने ज्ञान को प्रयोग में बदलने के अवसर चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि उनकी पृष्ठभूमि उनके भविष्य की सीमा निर्धारित नहीं करती। इसलिए हमें प्रतिभा को केवल शहर या पिनकोड के आधार पर मापना बंद करना होगा। किसी विद्यार्थी का गाँव,स्कूल की इमारत,भाषा या पारिवारिक आर्थिक स्थिति उसके सपनों की ऊँचाई निर्धारित नहीं करनी चाहिए। भारत को हर क्षेत्र से वैज्ञानिक प्रतिभा की आवश्यकता है—पहाड़ों, रेगिस्तानों,खेतों,मछुआरा बरितियों और छोटे शहरों से। हो सकता है कि भारत का अगला महान वैज्ञानिक इस समय किसी आईआईटी की कक्षा में न बैठा हो। संभव है कि वह किसी गाँव के स्कूल में पेड़ के नीचे बैठकर किसी कीोट को देख रहा हो,तारों का अध्ययन कर रहा हो, किसी मशीन की मरम्मत कर रहा हो या यह सोच रहा हो कि बारिश का पानी मिट्टी में गायब क्यों हो जाता है। वही प्रश्न उसकी वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत बन सकता है। विज्ञान का कोई शहरी पता नहीं होता। ज्ञान की कोई सामाजिक सीमा नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी पनप सकती है। यदि भारत को वास्तविक ज्ञान-समाज बनना है,तो उसे प्रतिभा की खोज केवल प्रतिष्ठित संस्थानों में ही नहीं।

कविता



प्रोफेसर राघव प्रताप कौशिक राहठक (हरियाणा)

आदमी जानवर बन गया है...

लोग लोमड़ी को बहुत चालाक कहते थे आदमी ने लोमड़ी को भी मात कर दिया है। जंगली जानवर मांस खाया करते हैं आदमी भी आजकल नॉन वेजेंटेरियन हो गया है। कुत्ते को हम आमतौर पर वफादार जानवर कहते हैं लेकिन आदमी धोखेबाज बनता जा रहा है! उल्लू के बारे में रात को जगाने की बात सुनते थे लेकिन आजकल तो आदमी उल्लू को मात कर रहा है। सभी पक्षी एक वृक्ष पर घोंसले बना इकट्ठे रहते हैं परिवार के सदस्य घर में इकट्ठे नहीं रहना चाहते। कोई भी जानवर खाने पीने की चीजें इकट्ठी नहीं करता आदमी है चीजों को इकट्ठा करने में जिंदगी बिता देता है। जानवर और पक्षी कभी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते आदमी एक दूसरे से भेद और नफरत करता है। सभी पक्षी और जानवर अपनी मेहनत का खाते पीते हैं एक आदमी है जो दूसरों का हक मार कर खुश होता है। परमात्मा ने तो हमें सबको ईंसान बनाकर भेजा था परंतु हम ईंसान तो नहीं बन सके जानवर जरूर बन गए हैं।

CMYK

नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा ने भरी हंकार

शिवपुर-चरचा में विशाल रैली के बाद साकेत सदन में चुनावी सभा



शिवपुर-चरचा में भाजपा का चुनावी शंखनाद विशाल रैली के बाद साकेत सदन में बनी रणनीति

विशाल रैली के बाद साकेत सदन में चुनावी सभा,बूथ से वार्ड तक संगठन मजबूत करने पर मंथन

सेवा,सुशासन और विकास के साथ चुनावी मैदान में उतरने का संकल्प

शिवपुर-चरचा में भाजपा का चुनावी शंखनाद,विशाल रैली के बाद साकेत सदन में बनी रणनीति

भाजपा ने कटी चुनावी कमर, शिवपुर-चरचा में रैली से शक्ति प्रदर्शन,सभा में बृथवार रणनीति

रैली से शक्ति प्रदर्शन,सभा में चुनावी रणनीति,शिवपुर-चरचा में भाजपा ने भरी हंकार

—संवाददाता—

बैकुंठपुर,06 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

नगर पालिका शिवपुर-चरचा के आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए संगठन की सक्रियता बढ़ा दी है,शिवपुर-चरचा में भाजपा की ओर से विशाल रैली निकाली गई,जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, रैली के बाद साकेत सदन में आयोजित वृहद संगठनात्मक एवं चुनावी सभा में आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। सभा में बृथ से लेकर वार्ड स्तर तक संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों सौंपने,मतदाताओं से निरंतर संपर्क बढ़ाने तथा पार्टी के अभियान को प्रत्येक मोहल्ले और घर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया, नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान करते हुए सेवा,सुशासन,विकास और संगठन की मजबूती को चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बताया, भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव केवल प्रत्याशी के भरोसे नहीं बल्कि संगठन की सामूहिक मेहनत से लड़ा जाएगा,इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने बूथ और वार्ड की जिम्मेदारी लेकर जनता के बीच लगातार संवाद स्थापित करना होगा।

विशाल रैली में दिखा कार्यकर्ताओं का उत्साह-शिवपुर-चरचा में आयोजित भाजपा की विशाल रैली के दौरान कार्यकर्ताओं

भारत माता और महापुरुषों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरुआत-

साकेत सदन में आयोजित वृहद संगठनात्मक एवं चुनावी सभा का शुभारंभ भारत माता, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, इसके बाद नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक चर्चा शुरू हुई, वार्डवार स्थिति, बृथ समितियों की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां, जनसंपर्क अभियान और आगामी चुनावी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, सभा में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि संगठन की चुनावी तैयारी बृथ स्तर तक मजबूत हो। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे और पार्टी के अभियान को जनता के बीच लेकर जाए।

में उत्साह देखने को मिला,बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर रैली में शामिल हुए और इसके बाद साकेत सदन में आयोजित चुनावी सभा में पहुंचे,रैली के माध्यम से पार्टी ने चुनावी अभियान को गति देने का संदेश दिया। कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव को लेकर चर्चा और तैयारियों का दौर तेज रहा, पार्टी नेताओं ने कहा कि संगठन की गतिविधियों को केवल बैठक और सभाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा,बल्कि वार्ड स्तर पर लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र में नागरिकों से संवाद करने,उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने तथा पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया गया।

संगठन और कार्यकर्ताओं की एकजुटता से मिलेगी जीत-भैयालाल राजवाड़े-बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नगर पालिका चुनाव संगठन और कार्यकर्ताओं की एकजुटता को परीक्षा है,उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया,उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है,उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच जाने की बात कही, भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि भाजपा ने विकास और जनसेवा को प्राथमिकता दी है, संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत चुनावी तैयारी का महत्वपूर्ण आधार है,

उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने का आह्वान किया।
बृथ की मजबूती ही चुनावी विजय का आधार-रामकुमार टोपों-नगर पालिका चुनाव प्रभारी एवं सीतापुर विधायक रामकुमार टोपों ने बृथ स्तर की तैयारी को चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण आधार बताया,उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने निर्धारित दायित्व का गंभीरता से निर्वहन करें। बृथ समितियों को सक्रिय करते हुए वार्ड स्तर पर संगठन की गतिविधियों को मजबूत किया जाना जरूरी है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर नागरिकों से संपर्क और संवाद बढ़ाने की बात कही,उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को समझना और उनके साथ सीधा संवाद स्थापित करना चुनावी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए,रामकुमार टोपों ने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियों के साथ मैदान में सक्रिय रहने का संदेश दिया, उनके अनुसार मजबूत बृथ,सक्रिय कार्यकर्ता और जनता से सीधा संपर्क चुनावी तैयारी के प्रमुख आधार हैं।

सेवा और सुशासन के दम पर हर वार्ड में जीत का लक्ष्य-देवेन्द्र तिवारी-भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने कहा कि पार्टी का संगठन और समर्पित कार्यकर्ता भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हैं,उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि नगर पालिका चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं को प्रत्याशी मानकर अपने बृथ और वार्ड की जिम्मेदारी संभाले,उन्होंने कहा कि भाजपा सेवा,सुशासन और विकास की राजनीति को लेकर जनता के बीच जाएगी, पार्टी के विकास कार्यों,जनकल्याणकारी योजनाओं और संगठन की सेवा भावना को नागरिकों तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं को

करना होगा, उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनावी अभियान में केवल बैठकों और कार्यक्रमों तक सीमित रहने के बजाय लगातार जनता के बीच संपर्क बनाए रखना होगा। प्रत्येक परिवार तक पहुंचने और नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने को प्राथमिकता देने की बात कही गई।

जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएं कार्यकर्ता : कृष्णबिहारी जायसवाल-प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णबिहारी जायसवाल ने कहा कि किसी भी चुनाव में संगठन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की विचारधारा,सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने का आह्वान किया,उन्होंने कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत बृथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से आती है। इसलिए प्रत्येक बृथ पर सक्रियता बढ़ाने और लोगों से निरंतर संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है,उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठित प्रयास के साथ चुनावी अभियान में जुटने का संदेश दिया।

हर स्तर पर समन्वय और जनसंपर्क जरूरी-फुलेश्वरी सिंह-नगर पालिका चुनाव सह प्रभारी फुलेश्वरी सिंह ने चुनावी तैयारियों में प्रत्येक स्तर पर समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने पर जोर दिया,उन्होंने कहा कि महिला,युवा,वरिष्ठ नागरिक और समाज के प्रत्येक वर्ग तक भाजपा कार्यकर्ताओं की पहुंच होनी चाहिए। वार्ड स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के साथ-साथ अधिक से अधिक जनसंपर्क करने की आवश्यकता है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच पार्टी का सकारात्मक संदेश पहुंचाने और संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने का आह्वान किया।

कार्यकर्ताओं का समर्पण भाजपा की वास्तविक शक्ति-रितेश गुप्ता-चुनाव सह प्रभारी रितेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत,समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा ही पार्टी की वास्तविक शक्ति है, उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर निर्धारित लक्ष्य के साथ कार्य करना होगा। बृथ और वार्ड स्तर पर संगठन जितना मजबूत होगा, चुनावी अभियान को उतनी ही

मजबूती मिलेगी, उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय बनाए रखते हुए चुनावी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपील की।

वार्डवार रणनीति पर हुआ व्यापक मंथन-साकेत सदन की चुनावी सभा में नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्डवार संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा की गई,बृथ समितियों की सक्रियता,कार्यकर्ताओं के दायित्व,मतदाताओं से संपर्क और आगामी चुनावी कार्यक्रमों को लेकर नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया,सभा में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रत्येक वार्ड में संगठन की स्थिति को मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो,नेताओं ने कहा कि चुनावी अभियान को केवल बैठकों तक सीमित रखने के बजाय इसे प्रत्येक वार्ड,मोहल्ले और घर तक पहुंचाना होगा,इसके लिए कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहकर नागरिकों से संपर्क और संवाद स्थापित करने की आवश्यकता बताई गई।

घर-घर संपर्क पर रहेगा जोर-भाजपा की चुनावी रणनीति में घर-घर संपर्क को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया,कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे अपने-अपने वार्ड में नागरिकों से व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाएं और जनता की समस्याओं तथा अपेक्षाओं को समझें, साथ ही केंद्र एवं छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई, सभा में यह संदेश बनाया कि चुनावी अभियान को प्रभावी बनाने के लिए बृथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता लगातार बनी रहनी चाहिए।

हर कार्यकर्ता को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी-सभा में दिए गए संदेशों से स्पष्ट रहा कि भाजपा नगर पालिका चुनाव में संगठन की सामूहिक ताकत के आधार पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है,बृथ समितियों से लेकर वार्ड स्तर तक कार्यक्रमों की भूमिका तय करने और उन्हें जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतारने पर जोर दिया गया,कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क बनाए रखने,पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया।

बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद-इस अवसर पर विधायक भैयालाल राजवाड़े, चुनाव प्रभारी एवं सीतापुर विधायक रामकुमार टोपों, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णबिहारी जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा, चुनाव सह प्रभारी फुलेश्वरी सिंह, रितेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष बसंत राय, राजेश सिंह, जिला महामंत्री पंकज गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष अरुण जायसवाल, जिला मंत्री प्रदीप तिवारी, जिला पंचायत सदस्य गीता राजवाड़े, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुन्ती चक्रधारी, जिला मीडिया प्रभारी तीर्थ राजवाड़े, एनजीओ प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कमलेश शर्मा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सतेन्द्र राजवाड़े, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष कृष्णा प्रजापति, मंडल अध्यक्ष दीपा विश्वकर्मा, शिक्षा प्रकोष्ठ जिला संयोजक गोकर्ण शुक्ला, महामंत्री मुना चक्रधारी, रणविजय सिंह, नगरीय निकाय प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक सचिन मलिक तथा सोशल मीडिया प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सोनालाल राजवाड़े सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रैली से चुनावी सभा तक संगठन ने दिखाया दम

शिवपुर-चरचा में विशाल रैली और इसके बाद साकेत सदन में हुई वृहद चुनावी सभा के जरिए भाजपा ने नगर पालिका चुनाव को लेकर अपनी संगठनात्मक सक्रियता का प्रदर्शन किया। सभा में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियों के साथ मैदान में उतरने और लगातार जनसंपर्क करने का संदेश दिया, पूरे कार्यक्रम में बृथ की मजबूती, वार्ड स्तर की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जनता से सीधे संवाद को चुनावी रणनीति का आधार बताया गया,अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैठक और रैली में तय की गई रणनीति किस तरह वार्ड और बृथ स्तर पर जमीन पर उतरती है, फिलहाल भाजपा ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में जुटने का संदेश दिया है और 'हर बृथ मजबूत-हर वार्ड में विजय' के संकल्प के साथ अपनी चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने की दिशा तय की है।

मेरे सपनों का भारत' में विद्यार्थियों ने रखी विकसित भारत की कल्पना

सेवा संकल्प अभियान के तहत राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता,40 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,06 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर में 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत 'मेरे सपनों का भारत' विषय पर महाविद्यालय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के विभिन्न संकायों और विभागों से 40 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपने भाषणों के माध्यम से विकसित,आत्मनिर्भर, समतामूलक, सशक्त और संवेदनशील भारत की अपनी कल्पना सामने रखी। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने केवल भारत की उपलब्धियों की चर्चा तक अपने विचार सीमित नहीं रखे, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर भी विचार रखे। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण,युवाओं की भूमिका,वैज्ञानिक दृष्टिकोण,सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्य, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण जैसे विषय भाषणों के प्रमुख केंद्र में रहे।

प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में विधि विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. तरुण कुमार राय, राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक अध्यापक विनोद कुमार गुप्ता और



भूगोल विभाग की सहायक अध्यापक दीपिका स्वर्णकार शामिल रहे। निर्णायकों ने प्रतिभागियों के विषय-वस्तु ज्ञान, तार्किकता, अभिव्यक्ति क्षमता, भाषण शैली, आत्मविश्वास और प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन किया। कार्यक्रम के आयोजन में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉ. कुलदीप चतुर्वेदी, विधि विभाग की सहायक प्राध्यापक पूनम सोनवानी, विधि विभाग के सहायक अध्यापक मोहन कश्यप, इतिहास विभाग के सहायक अध्यापक विक्रम खड़ा तथा भौतिकी के प्राध्यापक गोविंद प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन पूनम सोनवानी और डॉ. कुलदीप

चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भाषण जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों को केवल मंच पर अपनी बात रखने का अवसर नहीं देतीं, बल्कि उनमें अभिव्यक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करती हैं।

'मेरे सपनों का भारत' जैसे विषय विद्यार्थियों को व्यक्तिगत आकांक्षाओं को देश के व्यापक विकास से जोड़कर देखने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के समापन पर विनोद कुमार गुप्ता और दीपिका स्वर्णकार ने प्रतिभागियों के भाषणों की समीक्षा करते हुए उनके प्रस्तुतीकरण की सराहना की।

उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन और चिंतन के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

अंत में डॉ. कुलदीप चतुर्वेदी ने निर्णायक मंडल, आयोजन समिति के सदस्यों, महाविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और प्रतियोगिता में शामिल सभी छात्र-छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपने विचारों और सपनों को व्यक्त राष्ट्रीय संदर्भ में व्यक्त करने का मंच देती हैं। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण एवं प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हुआ।

कपड़े से निकला सांप पत्नी पर गिरा,प्रति की मौत

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,06 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

दरिद्रा थाना क्षेत्र के ग्राम झुमरपारा में जमीन पर सो रहे दंपति के साथ सोमवार रात सर्पदंश की घटना हो गई। पति के कपड़े से निकला जहरीला सांप पत्नी के शरीर पर जा गिरा। पत्नी ने सांप को झटककर अलग किया। इधर सर्पदंश से पीड़ित पति की मंगलवार सुबह अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम झुमरपारा निवासी धरम पिता बाबूलाल (40) सोमवार रात खाना खाने के बाद पत्नी के साथ जमीन पर सोया था। रात करीब 10 बजे धरम को दाहिने हाथ में कुछ काटने का एहसास हुआ। वह तत्काल उठा और कपड़े को खोलकर झाड़ा।

इसी दौरान कपड़े के अंदर छिपा सांप निकलकर उसकी पत्नी के शरीर पर जा गिरा। सांप देखकर पत्नी घबरा गई और उसे हाथ से झटककर शरीर से अलग किया।

मध्यान्ह भोजन रसोइयों ने सौंपा मांग पत्र मानदेय बढ़ाकर 10 हजार करने की मांग

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,06 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ मध्यान्ह भोजन रसोइया कल्याण संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है। संघ ने वर्तमान में मिल रहे 2 हजार रुपए मासिक मानदेय को बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। संघ की ओर से 6 अक्टूबर को सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत रसोइयों को बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलने वाला मानदेय काफी कम है। संघ ने शासन से रसोइयों को राहत प्रदान करने की मांग की है। मांग पत्र में कम से कम 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय निर्धारित करने, छत्तीसगढ़ के रसोइयों को वर्दी की सुविधा देने तथा जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन के हिसाब से समूहों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके अलावा स्कूलों में कार्यरत रसोइयों का पद स्कूल शिक्षा विभाग में दर्ज कर नियमित नियुक्ति प्रदान करने की मांग भी की गई है। संघ ने यह भी मांग रखी है कि रसोइयों को हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान किया जाए। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि कम मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए शासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द निर्णय ले। छत्तीसगढ़ में मध्यान्ह भोजन रसोइयों का मानदेय लंबे समय से मुद्दा बना हुआ है। वर्ष 2026 में रसोइया संघ ने मानदेय बढ़ाने को लेकर आंदोलन भी किया था।





कलेक्टर रेना जमील की तस्वीर ने छेड़ी नई सोच

जब आस्था बनी सामाजिक सद्भाव का संदेश कलेक्टर रेना जमील की तस्वीर चर्चा में...

जाति-धर्म की दीवारों से ऊपर इंसानियत, कलेक्टर रेना जमील की तस्वीर दे गई बड़ा संदेश

**पौधरोपण से पर्यावरण,
जलमिषेक से सद्भाव का संदेश
सूरजपुर से सामने आई एक तस्वीर**

**नशामुक्त समाज से सामाजिक सद्भाव
तक, कलेक्टर रेना जमील ने दिया
संवेदनशीलता का संदेश**

**आस्था अपनी-अपनी, सम्मान सबका—
सूरजपुर कलेक्टर की तस्वीर ने दिया
सामाजिक एकता का संदेश**

**एक तस्वीर, कई संदेश... पर्यावरण,
नशामुक्ति और इंसानियत की बात
कटती कलेक्टर रेना जमील**

**जब आस्था बनी इंसानियत का संदेश,
सूरजपुर में कलेक्टर रेना जमील की
तस्वीर ने खींचा ध्यान**

**महिलाओं के साथ पौधरोपण से नशामुक्त
समाज और पर्यावरण संरक्षण का संदेश,
सिद्धेश्वर मंदिर में जलमिषेक की तस्वीर
ने दिया सामाजिक सद्भाव का संकेत**

**—ऑफर पाण्डेय—
सूरजपुर, 06 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।**

समाज केवल नियमों और व्यवस्थाओं से नहीं चलता, बल्कि उन छोटे-छोटे उदाहरणों से भी दिशा पाता है, जो लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, आज जब समाज में जाति, धर्म, वर्ग और अलग-अलग पहचान को लेकर दूरियां दिखाई देती हैं, ऐसे समय में कुछ तस्वीरें बिना

पौधा लगाने से लेकर समाज को बचाने तक का संदेश

पौधरोपण को अक्सर केवल एक औपचारिक कार्यक्रम मान लिया जाता है, एक पौधा लगाया गया, फोटो खिंची और कार्यक्रम समाप्त—अगर सोच इतनी ही हो तो पौधरोपण का उद्देश्य अधूरा रह जाता है, लेकिन पौधा वास्तव में आने वाले वर्षों की जिम्मेदारी है, आज लगाया गया पौधा कल किसी बच्चे को छाया देगा, किसी परिवार को फल देगा, पर्यावरण को मजबूती देगा और प्रकृति के संतुलन में अपनी भूमिका निभाएगा, इसी तरह नशामुक्त समाज की बात भी केवल नारा लगाने से पूरी नहीं होगी, नशे का असर एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। उसका असर परिवार की आर्थिक स्थिति, बच्चों के भविष्य, घरेलू वातावरण और अंततः पूरे समाज पर पड़ सकता है, इसलिए पर्यावरण बचाने और समाज को नशे से बचाने—दोनों की लड़ाई मूल रूप से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है, यही वजह है कि महिलाओं के साथ पौधरोपण और नशामुक्त समाज का संदेश एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदर्भ पैदा करता है।

किसी लंबे भाषण के भी बड़ा संदेश दे जाती हैं, सूरजपुर की कलेक्टर रेना जमील की सामने आई एक तस्वीर भी इसी तरह का संदेश देती नजर आती है। तस्वीर में कलेक्टर महिलाओं के साथ एक धार्मिक परिसर में दिखाई दे रही हैं, सामने भगवान शिव का मंदिर है और वहां जलमिषेक की प्रक्रिया चल रही है, यह तस्वीर केवल एक धार्मिक गतिविधि का दृश्य नहीं है, बल्कि इसे व्यापक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके भीतर आस्था, सामाजिक सहभागिता, महिलाओं की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्त समाज और आपसी सम्मान जैसे कई संदेश एक साथ दिखाई देते हैं, इससे पहले महिलाओं के साथ पौधरोपण करते हुए दिया गया संदेश भी इसी विचार को आगे बढ़ाता है, एक तरफ पौधा लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी का प्रतीक है तो दूसरी तरफ नशे से दूर रहने का संदेश परिवार और समाज के भविष्य से जुड़ा विषय है, इन दोनों संदेशों को एक साथ देखने पर बात केवल किसी एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं

रहती, बल्कि यह सवाल सामने आता है कि हम अपने समाज को आखिर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? महिलाएं बदलाव की सबसे मजबूत कड़ी—किसी भी समाज में स्थायी बदलाव केवल प्रशासनिक आदेशों से नहीं आता, परिवार से लेकर समाज तक महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, घर में बच्चों की आदतों, संस्कारों और सोच पर सबसे पहला प्रभाव परिवार का होता है, यदि परिवार नशे के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो, यदि माता-पिता बच्चों से संवाद करें, यदि समाज युवाओं को सही दिशा दिखाए, तो नशे जैसी समस्या के खिलाफ लड़ाई कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है, इसीलिए महिलाओं की सहभागिता केवल कार्यक्रम की भागीदारी नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है, आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं को केवल कार्यक्रमों की दर्शक या सहभागी के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जाए।

और फिर सामने आई वह तस्वीर...

इसी पूरे संदर्भ के बीच सिद्धेश्वर मंदिर परिसर की वह तस्वीर अपने आप में एक अलग संदेश देती है, तस्वीर में कलेक्टर रेना जमील भगवान शिव के मंदिर में जलमिषेक के दौरान दिखाई दे रही हैं और आसपास महिलाएं मौजूद हैं, इस तस्वीर को किसी व्यक्ति की निजी धार्मिक आस्था के रूप में परिभाषित करना उचित नहीं होगा, लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह तस्वीर एक अलग संदेश जरूर देती है—समाज में अलग-अलग पहचान रखने वाले लोगों के बीच सम्मान और सहभागिता की जगह बनी रहनी चाहिए, किसी की व्यक्तिगत पहचान, पृष्ठभूमि या आस्था कुछ भी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ संवाद और सम्मान लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यही वह बिंदु है जहां तस्वीर एक साधारण तस्वीर से आगे बढ़कर एक विचार बन जाती है।

धर्म से ऊपर इंसानियत का सवाल—हमारे समाज में धर्म और आस्था का अपना महत्व है, लोग अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन जब धार्मिक पहचान को इंसान की पहचान से बड़ा बना दिया जाता है, तब समाज में दूरी पैदा होने लगती है, दूसरी ओर यदि यही आस्था लोगों को जोड़ने, एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का माध्यम बने तो उसका प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, सिद्धेश्वर मंदिर परिसर की तस्वीर को इसी व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा संदेश यही हो सकता है कि—आस्था अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत अलग नहीं होनी चाहिए, पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एक-दूसरे के सम्मान का तरीका समान होना चाहिए, पहचान अलग हो सकती है, लेकिन

समाज के प्रति जिम्मेदारी साझा हो सकती है।

आज समाज को इसी सोच की जरूरत है—आज सोशल मीडिया के दौर में छोटी-सी बात भी विवाद का कारण बन जाती है, जाति, धर्म, राजनीतिक विचार या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर लोगों को अलग-अलग खांचों में देखने की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देती है, ऐसे वातावरण में जरूरत उन उदाहरणों की है जो लोगों को यह याद दिलाएं कि समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे की आस्था का सम्मान करता है, यदि कोई अधिकारी समाज के लोगों के बीच सहजता से खड़ा होता है, यदि महिलाएं पर्यावरण और नशामुक्ति जैसे विषयों पर आगे आती हैं और यदि प्रशासन तथा समाज मिलकर सकारात्मक संदेश देता है, तो यह केवल एक कार्यक्रम नहीं रहता, यह सामाजिक संवाद की शुरुआत बन सकता है।

नशामुक्त समाज और पर्यावरण—दोनों लड़ाइयां भविष्य के लिए—एक ओर आज समाज नशे की समस्या से जुड़ा रहा है, दूसरी ओर पर्यावरण लगातार दबाव में है। दोनों समस्याओं की सबसे बड़ी मार आने वाली पीढ़ियों को झेलनी पड़ सकती है, नशा परिवारों को भीतर से कमजोर करता है और पर्यावरण का नुकसान जीवन की प्राकृतिक परिस्थितियों को प्रभावित करता है, इसलिए यदि एक ही मंच से नशामुक्त समाज और पर्यावरण संरक्षण का संदेश सामने आता है तो उसे केवल औपचारिक गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जरूरत इस बात की है कि ऐसे संदेश गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और परिवार-परिवार तक पहुंचें।

बड़ा सवाल—क्या हम तस्वीर का संदेश समझ पाएंगे?—किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग उपस्थित हुए या कितने

पौधे लगाए गए, असल सफलता तब होगी जब लगाया गया पौधा बचाया जाए, असल सफलता तब होगी जब नशे की गिरफ्त में जा रहे किसी युवा को परिवार समय रहते रोक सके, असल सफलता तब होगी जब माता-पिता अपने बच्चों से संवाद करें, असल सफलता तब होगी जब समाज किसी व्यक्ति को उसकी जाति या धर्म से पहले इंसान के रूप में देखे, और असल सफलता तब होगी जब धार्मिक स्थल लोगों को बांटने के बजाय सम्मान, सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश देने वाले स्थान बनें।

तस्वीर से बड़ा संदेश यही—पहचान से पहले इंसानियत—सूरजपुर से सामने आई यह तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसे केवल एक व्यक्ति की मंदिर में मौजूदगी के रूप में देखने के बजाय व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जा सकता है, महिलाओं के साथ पौधरोपण—पर्यावरण बचाने का संदेश, नशामुक्त समाज की बात—परिवार और युवा पीढ़ी को बचाने का संदेश, धार्मिक परिसर में सहभागिता—सामाजिक सम्मान और संवाद का संदेश, और इन सबको जोड़कर निकलने वाला संदेश—समाज को जोड़कर रखने के लिए इंसानियत सबसे बड़ी कड़ी है, आज जरूरत इसी सोच को आगे बढ़ाने की है, क्योंकि समाज तब मजबूत नहीं होता जब सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, समाज तब मजबूत होता है जब अलग-अलग सोच और पहचान रखने वाले लोग एक-दूसरे के अस्तित्व और सम्मान को स्वीकार करते हुए साथ खड़े होते हैं, शायद यही वजह है कि कभी-कभी एक तस्वीर कुछ शब्दों से ज्यादा प्रभाव छोड़ जाती है, क्योंकि तस्वीर में दिखाई देने वाला दृश्य कुछ शब्दों का होता है, लेकिन उससे निकलने वाला सामाजिक संदेश पीढ़ियों तक पहुंच सकता है।

कोरिया : उपेक्षा का दंश, अब संभाग बनाने की उठी पुरजोर मांग

समाजसेवी साहित्यकार संवर्त कुमार 'रूप' ने कहा—भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक विरासत और क्षेत्रीय जरूरतों के लिहाज से कोरिया को संभाग का दर्जा देने पर हो गंभीर विचार

**—रवि सिंह—
कोरिया/बैकुण्ठपुर, 06 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।**

छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में कोरिया को संभाग बनाने की मांग एक बार फिर चर्चा में है, समाजसेवी एवं साहित्यकार संवर्त कुमार रुद्र प्रसाद 'रूप' ने कोरिया की वर्तमान स्थिति, भौगोलिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक पहचान और प्रशासनिक जरूरतों को सामने रखते हुए जिले को संभाग का दर्जा देने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है।

उनका कहना है कि 28 मई 1998 को जिला बनने के बाद कोरियावासियों ने विकास और बेहतर प्रशासन की उम्मीद की थी, लेकिन समय के साथ हुए प्रशासनिक पुनर्गठन और जिले के भू-भाग में कमी के कारण क्षेत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उनका तर्क है कि कोरिया को संभाग का दर्जा मिलने से केवल बैकुण्ठपुर या कोरिया जिले को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों का नया केंद्र विकसित हो सकता है, वर्तमान में कोरिया जिला सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, जबकि जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिले में वर्तमान में दो विकासखंड और चार तहसील हैं।

विभाजन के बाद बदली तस्वीर पर उठाए सवाल—संवर्त कुमार 'रूप' का कहना है कि पूर्ववर्ती प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद कोरिया का स्वरूप काफी बदल गया, उनके अनुसार पहले पांच विकासखंडों वाले जिले का भूगोल बाद में सीमित होकर कोरिया और सोनहत तक रह गया, वे इसे क्षेत्र के विकास की दृष्टि से असमान

पुनर्गठन मानते हैं, उनका कहना है कि प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव का असर केवल नशे तक सीमित नहीं रहता, इसका प्रभाव राजस्व, रोजगार, व्यापार, प्रशासनिक गतिविधियों और निवेश की संभावनाओं पर भी पड़ता है, उनके अनुसार क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने से युवाओं का दूसरे शहरों और राज्यों की ओर पलायन चिंता का विषय बन रहा है, वहीं प्रशासनिक गतिविधियां सीमित होने से स्थानीय बाजार और व्यापार पर भी इसका प्रभाव पड़ने की बात वे रखते हैं।

पुरानी विरासत और जर्जर ढांचे का भी मुद्दा—संवर्त कुमार 'रूप' ने कोरिया की ऐतिहासिक विरासत और पुराने भवनों की स्थिति को भी अपनी मांग से जोड़ा है, उनका कहना है कि पुराने सिविल लाइन क्षेत्र, न्यायालय-तहसील से जुड़े पुराने भवन तथा ऐतिहासिक रामानुज क्लब जैसी इमारतों का संरक्षण जरूरी है, उनके अनुसार कोरिया केवल एक प्रशासनिक जिला नहीं, बल्कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला क्षेत्र है, इसलिए विकास की योजना में आधुनिक अद्योसंरचना के साथ पुरानी विरासत के संरक्षण को भी स्थान मिलना चाहिए।

संभाग बनने से क्या बदल सकता है?—'रूप' का तर्क है कि संभाग का दर्जा केवल प्रशासनिक नाम बदलने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न विभागों और संस्थाओं का विस्तार हो सकता है, उनका कहना है कि यदि कोरिया को संभाग बनाया जाता है तो यहां प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना, रोजगार के नए अवसर और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की

संभावनाएं बन सकती हैं, हालांकि संभाग बनने से मेडिकल कॉलेज, सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल या औद्योगिक कॉरिडोर स्वतः स्थापित होना अनिवार्य नहीं है, इन संस्थानों के लिए अलग-अलग शासन स्तर के निर्णय, बजट और स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इसलिए इन संभावनाओं को मांग रखने वाले पक्ष की अपेक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए।

'उत्तर छत्तीसगढ़ की नई इकोनॉमिक कैपिटल' बनाने की सोच—संवर्त कुमार 'रूप' का कहना है कि कोरिया की स्थिति ऐसी है कि यदि इसे संभागीय मुख्यालय के रूप में विकसित किया जाए तो बैकुण्ठपुर क्षेत्र आसपास के जिलों के लिए भी आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बन सकता है, उनके शब्दों में, 'यदि कोरिया को संभाग बनाया जाता है तो यह केवल बैकुण्ठपुर या कोरिया का विकास नहीं होगा, बल्कि उत्तर छत्तीसगढ़ की एक नई इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में अपने की संभावना बनेगी, उनका मानना है कि इससे आसपास के क्षेत्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन और प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ मिल सकता है।

भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक पहचान को आधार—संवर्त कुमार 'रूप' ने कोरिया की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक महत्ता, निश्चित भू-भाग और अवसर की समता को संभाग बनाए जाने के पक्ष में प्रमुख आधार बताया है, उनका कहना है कि किसी क्षेत्र के प्रशासनिक पुनर्गठन का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सीमाएं निर्धारित करना नहीं, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना होना चाहिए, इसी आधार पर वे कोरिया को



संभाग बनाने की मांग को केवल स्थानीय मांग न मानकर उत्तर छत्तीसगढ़ के व्यापक विकास से जोड़कर देखने की अपील कर रहे हैं।

मुद्दा अब प्रशासनिक निर्णय से आगे जनचर्चा का—कोरिया को संभाग बनाने की मांग पर अंतिम निर्णय शासन स्तर पर होना है, इसके लिए क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्रशासनिक आवश्यकता, आर्थिक क्षमता, मौजूदा संभागीय संरचना, वित्तीय प्रभाव और आसपास के जिलों पर संभावित प्रभाव जैसे विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जरूरी होगा, फिलहाल संवर्त कुमार

'रूप' ने क्षेत्र की जनता से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और अपनी आवाज उठाने का आह्वान किया है, उनका कहना है कि कोरिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब यह सवाल केवल एक जिले की प्रशासनिक पहचान का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्षेत्र के विकास की दिशा तय करने का सवाल है।

कमी संसाधनों की नहीं, प्रशासनिक इच्छाशक्ति की है—संवर्त कुमार 'रूप' का कहना है कि कोरिया के पास प्राकृतिक संसाधन, ऐतिहासिक पहचान और पर्याप्त भू-क्षेत्रीय

संभावनाएं हैं, आवश्यकता इस बात की है कि इन क्षमताओं को योजनाबद्ध तरीके से विकास में बदला जाए, उनके अनुसार कमी संसाधनों की नहीं, प्रशासनिक इच्छाशक्ति की है, अब सवाल यह है कि कोरिया को संभाग बनाने की मांग भविष्य में कितनी व्यापक जनसमर्थन प्राप्त करती है और शासन इस प्रस्ताव को किन प्रशासनिक एवं वित्तीय मानकों पर परखता है, फिलहाल इस मांग ने कोरिया के भविष्य, प्रशासनिक पहचान और क्षेत्रीय विकास को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है।



कल 8 अक्टूबर को खुलेगा सजा का पन्ना, डबल मर्डर के चार दोषियों पर टिकी सूरजपुर की निगाहें

8 अक्टूबर का इंतजार खत्म होने को... डबल मर्डर के दोषियों की सजा पर कल फैसला

- कल तय होगी चार दोषियों की सजा, साथ ही उठी मुख्य आरोपी की जेल बदलने की मांग...
- डबल मर्डर : चार दोषी करार, कल सजा का फैसला; जेल बदलने की मांग ने बढ़ाए सवाल
- सजा कल, सवाल आज भी कई : मुख्य आरोपी की जेल बदलने की मांग क्यों?
- चार दोषी, कल सजा का दिन... अबिकापुर जेल से शिफ्टिंग की मांग ने खींचा ध्यान
- अदालत में कल सजा, जेल प्रशासन के सामने भी चुनौती—कुलदीप को दूसरी जेल भेजने की मांग...



—संवाददाता—
सूरजपुर, 06 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

दो साल से सूरजपुर की स्मृति में जिंदा बहुचर्चित दोहरा हत्याकांड में अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं, कल 8 अक्टूबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोषसिद्ध चार आरोपियों की सजा तय होगी है, 28 सितंबर को अदालत ने कुलदीप साहू, फूल सिंह उर्फ रिंकू सिंह, चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को दोषी करार दिया था, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अदालत अपराध की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पूरे मामले की परिस्थितियों को देखते हुए दोषियों को कितनी और कैसी सजा निर्धारित करती है। लेकिन 8 अक्टूबर का दिन केवल सजा के सवाल तक सीमित नहीं है, इसके साथ ही मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को अबिकापुर केंद्रीय जेल से किसी अन्य उच्च सुरक्षा वाली जेल में स्थानांतरित किए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है, सवाल यह उठ रहा है कि जिस मामले ने पूरे जिले को झकझोर दिया, उसके मुख्य दोषसिद्ध आरोपी को उसी जेल में रखा जाना उचित है या उसकी सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए जेल प्रशासन को स्थानांतरण पर विचार करना चाहिए?

दो साल बाद दोषसिद्ध, अब सजा की बारी— सूरजपुर के इस दोहरा हत्याकांड ने घटना के समय पूरे क्षेत्र को हिला दिया था, मामले की जांच, साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और न्यायालयीन सुनवाई के बाद मामला अब सजा के चरण तक पहुंच चुका है, अदालत द्वारा चार आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद अब 8 अक्टूबर को यह स्पष्ट होगा कि न्यायालय दोषसिद्ध आरोपियों के लिए कानून के तहत कौन-सी सजा निर्धारित करता है, शहर में एक वर्ग की ओर से कठोरता सजा की मांग की जा रही है, हालांकि सजा कितनी होगी, इसका अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी, इसलिए 8 अक्टूबर के आदेश से पहले किसी निश्चित सजा का अनुमान लगाना न्यायिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा।

सजा के साथ जेल बदलने की मांग क्यों?—सजा के इंतजार के बीच मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के वर्तमान जेल स्थान को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, कुलदीप वर्तमान में अबिकापुर केंद्रीय जेल में निरुद्ध है, इससे पहले पुलिस पर वाहन चढ़ाकर जान से मारने के प्रयास से जुड़े मामले में उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, अब शहर

मोबाइल से लेकर मुलाकात तक—जेल व्यवस्था पर सवाल

मुख्य आरोपी को जेल में कथित रूप से नियम विरुद्ध सुविधाएं मिलने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, इनमें मोबाइल का उपयोग, बाहर से भोजन मंगाने, बिना निर्धारित प्रक्रिया के लोगों से मुलाकात और बैरक से बाहर घूमने जैसी बातें शामिल हैं, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस सामग्री में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनका सत्यापन सीसीटीवी फुटेज, मुलाकात रजिस्टर, जेल रिकॉर्ड, तलाशी कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों की जांच से ही हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यदि ऐसे आरोप किसी सामान्य बंदी को लेकर होते तो क्या जेल प्रशासन इसे सामान्य शिकायत मानकर छोड़ सकता था? और जब मामला पहले से ही इतना संवेदनशील हो, तब क्या ऐसी शिकायतों की तत्काल और निष्पक्ष जांच जरूरी नहीं हो जाती? यही वजह है कि जेल व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल अब केवल आरोपी तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि पूरी जेल सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तक पहुंच रहे हैं।

के कुछ लोगों और पीड़ित पक्ष से जुड़े लोगों की ओर से मांग उठ रही है कि उसे अबिकापुर जेल से हटाकर किसी अन्य उच्च सुरक्षा वाली जेल में रखा जाए, मांग करने वालों का तर्क है कि मामला अत्यंत संवेदनशील है और मुख्य आरोपी के संबंध में जेल के भीतर कथित तौर पर विशेष सुविधाएं मिलने के आरोप समय-समय पर उठते रहे हैं, ऐसे में जेल बदलने से सुरक्षा व्यवस्था और जेल प्रशासन की निगरानी दोनों को लेकर पैदा हो रहे सवालों को दूर किया जा सकता है।

सामान्य बंदी पर नियम, गंभीर मामले में अलग व्यवस्था क्यों?— लोगों की ओर से उठया जा रहा सवाल सीधा है—यदि जेल में सामान्य बंदियों के लिए मोबाइल, बाहरी भोजन, मुलाकात और बैरक से बाहर जाने को लेकर सख्त नियम हैं तो किसी संवेदनशील और चर्चित मामले के दोषसिद्ध आरोपी को लेकर किसी भी प्रकार की कथित रियायत की शिकायत क्यों सामने आनी चाहिए? यदि आरोप गलत हैं तो जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकती है, लेकिन यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो यह केवल एक बंदी को सुविधा देने का मामला नहीं होगा, बल्कि जेल प्रशासन की निगरानी और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा, इसीलिए मांग उठ रही है कि जेल प्रशासन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी की सुरक्षा और संपर्कों की समीक्षा करे।

क्या 8 अक्टूबर के आदेश में जेल बदलने का फैसला होगा?—यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक अंतर समझना जरूरी है, अदालत 8 अक्टूबर को दोषसिद्ध आरोपियों की सजा निर्धारित करेगी, जबकि जेल में किस बंदी को किस कारागार में रखा जाना है, यह अलग प्रशासनिक प्रक्रिया का विषय है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि सजा

सुनाते समय अदालत अपने आदेश में जेल स्थानांतरण का निर्देश दे, यदि जेल बदलने की आवश्यकता महसूस होती है तो संबंधित समय कारागार प्रशासन और शासन स्तर पर उस पर निर्णय लिया जा सकता है, इसका अर्थ यह है कि 8 अक्टूबर को दो अलग-अलग स्तरों पर घटनाक्रम पर नजर रहेगी—अदालत में सजा का फैसला और जेल प्रशासन के स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था।

कुलदीप के खिलाफ कार्रवाई का पुराना सिलसिला भी चर्चा में—इस पूरे मामले को समझने के लिए घटना से पहले कुलदीप और उसके परिवार से जुड़े घटनाक्रम भी महत्वपूर्ण हैं, आपके उपलब्ध विवरण के अनुसार, कुलदीप का जिला बदर हुआ था, उसके चाचा के खिलाफ भी जिला बदर की कार्रवाई हुई और जिला बदर आदेश के उल्लंघन पर एफआईआर कर जेल भेजे जाने की कार्रवाई हुई, इसके बाद कुलदीप के पिता अशोक साहू का जिला बदर, उसके भाई संदीप साहू के खिलाफ एफआईआर और तत्काल गिरफ्तारी तथा पूर्व में चोरी के मामले में अशोक साहू के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जैसे घटनाक्रम सामने आते हैं, इन कार्रवाइयों के चलते कुलदीप और पुलिस के बीच टकराव बढ़ने की बात सामने आई, इसी पृष्ठभूमि में पुलिस के खिलाफ हमले की योजना बनाए जाने का आरोप सामने आया, घटना के कुछ दिन पहले चंद्रकांत चौधरी को भी सूरजपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के शोषण से जुड़े मामले में जेल भेजे जाने का उल्लेख किया गया है, इस तरह पुलिस और आरोपियों से जुड़े लोगों के बीच टकराव का पृष्ठभूमि को भी इस मामले की पूरी कहानी में नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

क्या पुलिस कार्रवाई ने खत्म कर दिया था अवैध गतिविधियों का रास्ता?—

घटना के बाद पुलिस के खिलाफ कई तरह के आरोप और प्रचार सामने आने की बात कही जाती रही, लेकिन दूसरी ओर पुलिस का दावा और उपलब्ध घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि कुलदीप और उसके परिवार से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा था, जिला बदर, उसके उल्लंघन पर कार्रवाई, परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी तथा पुराने मामलों में पुलिस कार्रवाई—इन सबको एक साथ देखा जाए तो यह सवाल जरूर उठता है कि क्या पुलिस की लगातार कार्रवाई से कुलदीप के प्रभाव और कथित अवैध गतिविधियों पर शिंकंका कम रहा था और इसी टकराव ने बाद में गंभीर रूप ले लिया? हालांकि इसे अंतिम रूप से घटना का उद्देश्य तभी माना जा सकता है जब न्यायालय के आदेश या प्रमाणित जांच रिकॉर्ड में इसकी स्पष्ट पुष्टि हो, इसलिए इसे घटनाक्रम और उपलब्ध आरोपों के संदर्भ में उठे सवाल के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

क्या शहर का 'डॉन' बनने की कोशिश थी?—इसी पूरी पृष्ठभूमि से एक और सवाल निकलता है की क्या कुलदीप सूरजपुर में अपने प्रभाव और दबदबे का ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें पुलिस की कार्रवाई को भी चुनौती दी जा सके? जिला बदर के बावजूद वापसी, आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई, परिवार पर पुलिस कार्रवाई और उसके बाद पुलिस के साथ बढ़ता टकराव इस सवाल को जन्म देता है कि क्या 'डॉन' बना चाहता था? क्या लगातार पुलिस कार्रवाई के बाद कुलदीप ने कानून को चुनौती देने की मानसिकता विकसित कर ली थी, या यह मामला बढ़ते अपराधिक टकराव का परिणाम था? इस सवाल का अंतिम उत्तर न्यायालय के आदेश और प्रमाणित रिकॉर्ड से ही निकलेगा।

विवेचना की भी हुई अग्निपरीक्षा— इस मामले में दोषसिद्ध तक पहुंचना केवल आरोप लगाने की प्रक्रिया नहीं थी, इसके पीछे पुलिस की विवेचना, साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और अभियोजन की न्यायालयीन पैरवी की भूमिका रही होगी, मामले के विवेचना अधिकारी

निरक्षक एवं तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी सूरजपुर विमलेश दुबे थे, उनके नेतृत्व में जुटाए गए साक्ष्यों और जांच के आधार पर प्रकरण न्यायालय तक पहुंचा, अब सजा के स्तर पर भी विवेचना और अभियोजन की मजबूती पर नजर रहेगी, यदि न्यायालय अपराध की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कठोर सजा निर्धारित करता है तो इसे जांच और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रभावशीलता के संदर्भ में भी देखा जाएगा, वहीं यदि न्यायालय कोई दूसरी सजा निर्धारित करता है तो उसके आधार और कारण 8 अक्टूबर के विस्तृत न्यायिक आदेश से ही स्पष्ट होंगे।

क्या दोषसिद्ध के बाद भी जेल में हिलाई की गुंजाइश?— यही वह सवाल है जो अब जेल प्रशासन के सामने खड़ा किया जा रहा है, दोषसिद्ध के बाद आरोपी की स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है, ऐसे में यदि उसके जेल में रहने को लेकर मोबाइल या विशेष सुविधाओं की शिकायतें हैं तो उनका परीक्षण होना चाहिए, मांग करने वालों का कहना है कि मुख्य आरोपी को अबिकापुर से हटाकर रायपुर, बिलासपुर या कि सी अन्य

सरकार और पुलिस मुख्यालय के लिए भी या चुनौतीपूर्ण मामला

इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले की मॉनिटरिंग किए जाने की बात सामने आई, वर्तमान आईजी दीपक झा तथा पूर्व और वर्तमान एसपी क्रमशः प्रशांत ठाकुर और योगेश पटेल द्वारा मामले की निगरानी की गई, शासन स्तर पर विशेष लोक अभियोजक सुरेश शर्मा को भी मामले की पैरवी के लिए नियुक्त किए जाने की जानकारी है, इससे साफ है कि मामला केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं रहा, बल्कि पुलिस विभाग और शासन के सामने भी इसे न्यायालय में मजबूती से प्रस्तुत करना एक चुनौती के रूप में देखा गया, अब चार आरोपियों की दोषसिद्धि के बाद उस चुनौती का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका है, 8 अक्टूबर की सजा इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया का अगला निर्णायक पड़ाव होगा।

उपयुक्त उच्च सुरक्षा वाले कारागार में स्थानांतरित की जांच की मांग भी की जा रही है, लेकिन यहां भी सवाल यही है कि क्या आरोपों की जांच हुई? यदि हुई तो उसका निष्कर्ष क्या है? और यदि नहीं हुई तो जांच कब होगी? यही सवाल है जिनका जवाब जेल प्रशासन से



अपेक्षित है।

8 अक्टूबर: सजा का दिन या कई सवालों के जवाब का इंतजार?— कल 8 अक्टूबर को अदालत का आदेश केवल चार दोषियों की सजा तय करेगा, लेकिन इसके साथ सूरजपुर के सामने कई सवाल खड़े रहेंगे, सजा कितनी होगी? क्या अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कठोरता सजा दी जाएगी? क्या अभियोजन के साक्ष्य सजा के स्तर पर भी उतने ही प्रभावी साबित होंगे? मुख्य आरोपी को अबिकापुर जेल में ही रखा जाएगा या जेल प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से स्थानांतरण पर फैसला करेगा? जेल में नियम विरुद्ध सुविधाओं के आरोपों की जांच होगी या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब अलग-अलग स्तर पर सामने आएंगे, एक बात निश्चित है—सजा का फैसला अदालत करेगी, जेल का फैसला सक्षम प्रशासन करेगा और आरोपों की सच्चाई जांच से सामने आएगी, दो साल से इस मामले पर नजर बनाए हुए 'दैनिक घटती-घटना' के लिए भी 8 अक्टूबर केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस पूरे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसकी शुरुआत घटना से हुई, फिर जांच, गिरफ्तारी, आरोप, न्यायालयीन सुनवाई और अब दोषसिद्ध तक पहुंची है, अब शहर की निगाह अदालत पर है, कल 8 अक्टूबर को फैसला बताएगा कि चार दोषसिद्ध आरोपियों के अपराध को न्यायालय ने किस गंभीरता से देखा और कानून के तहत उनके लिए कौन-सी सजा निर्धारित की।

सिंगापुर में छत्तीसगढ़ ने कौशल विकास के लिए किया एमओयू, एगो प्रोसेसिंग में 350 करोड़ का नया निवेश

उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को तैयार करने ITE Education Services के साथ समझौता



रायपुर, 06 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सिंगापुर यात्रा के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ ने कौशल विकास और निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। प्रदेश के युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए सिंगापुर की ITE Education Services के साथ एमओयू किया गया। वहीं एगो एवं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 350 करोड़ का नया निवेश प्रस्ताव भी मिला। इसके साथ ही सिंगापुर यात्रा में छत्तीसगढ़ को मिले एफडीआई निवेश प्रस्तावों की राशि बढ़कर 43,600 करोड़ हो गई है।

मुख्यमंत्री साय ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की। इसके अलावा दुनिया की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश और साझेदारी की

युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाली स्किलिंग पर जोर

विष्णु देव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार और ITE Education Services, Singapore के बीच तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल ने ITE कॉलेज का भ्रमण कर वहां के उद्योग आधारित प्रशिक्षण मॉडल को भी समझा। सिंगापुर में Cisco, BYD और Singapore Airlines जैसी बड़ी कंपनियां ITE कॉलेजों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रशिक्षण देने और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में सहयोग करती हैं। इसी अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ में भी लिया जाएगा। इससे उद्योगों की जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रशिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 'निवेश से उद्योग आते हैं और कुशल युवा उन उद्योगों की ताकत बनते हैं। सिंगापुर ने कौशल विकास का एक सफल मॉडल तैयार किया है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी उद्योगों की जरूरत के मुताबिक आधुनिक प्रशिक्षण मिले और वे अपने प्रदेश में ही बेहतर करियर बना सकें। प्रदेश में आने वाले उद्योगों को उनकी जरूरत के अनुसार कुशल युवा यहीं मिलें।

संभावनाओं पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ ने विदेश

Singapore-India Network for Growth (SING) Forum 2026 में भाग लिया है।

किसानों की उपज को मिलेगा बड़ा बाजार : मुख्यमंत्री साय ने सिंगापुर की Valency International Pte Ltd को छत्तीसगढ़ में 350 करोड़ के निवेश का आमंत्रण दिया। 22 देशों में कारोबार करने वाली यह कंपनी प्रदेश में इंटीग्रेटेड एगो एवं फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब स्थापित करेगी। इस हब में काजू, तिल, दलहन और मूंगफली की प्रोसेसिंग की जाएगी। इससे किसानों की उपज का प्रदेश में ही मूल्य संवर्धन होगा, उन्हें नए बाजार मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

सिंगापुर के विदेश मंत्री से हुई मुलाकात : मुख्यमंत्री साय ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों के बीच छत्तीसगढ़ और सिंगापुर के बीच निवेश, कौशल विकास, शहरी

नियोजन और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सिंगापुर के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ के विकास में किस तरह लिया जा सकता है, इस पर भी विचार-विमर्श हुआ।

15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के साथ निवेश पर चर्चा : सीईओ राउंडटेबल में मुख्यमंत्री साय ने 15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इनमें TCS, SMBC, Tolaram Group, Agropcor, Indian Ocean Group और Blue Aqua शामिल थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें छत्तीसगढ़ की निवेश-अनुकूल नीतियों, सुधारों और बेहतर कारोबारी वातावरण की जानकारी दी। बैठक में टेक्नोलॉजी, बैकिंग, एग्रीबिजनेस, एक्वाकल्चर और फूड सेक्टर में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

AI और डिजिटल फाइनेंस में युवाओं को प्रशिक्षण देने पर चर्चा : मुख्यमंत्री साय ने Global Finance & Technology Network (GFTN) के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। बैठक में GFTN के ग्रुप सीईओ Sopnendu Mohanty, इंडिया, एशिया, जापान एवं ASEAN के सीईओ James Boey और चीफ ऑफरिंग ऑफिसर Anthony Thomas सहित उनकी टीम शामिल हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के युवाओं को AI और डिजिटल फाइनेंस में प्रशिक्षण देने, प्रदेश के स्टार्टअप को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने और नई तकनीकों के लिए टेक लैब स्थापित करने में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इन महत्वपूर्ण समझौतों और बैठकों के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सिंगापुर यात्रा संपन्न हुई।

कोयला घोटाला : चार्जशीट में कवि कुमार विश्वास को 25 लाख भुगतान का जिक्र विधायक देवेन्द्र यादव-सूर्यकांत तिवारी की चैट से खुलासा



रायपुर, 06 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की ओर से पेश किए गए पूरक चालान में कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। चार्जशीट में देश के चर्चित कवि डॉ. कुमार विश्वास को कार्यक्रम के लिए 25 लाख रुपये के भुगतान का भी उल्लेख है। जांच एजेंसी की मुताबिक, यह रकम कोयला घोटाले से जुड़ी राशि से दिया गया है। चार्जशीट में दर्ज जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस शासनकाल के दौरान 'हमर भांचा राम' कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में देश के कई चर्चित कवियों को आमंत्रित किया गया था। जांच में सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, कार्यक्रम से संबंधित खर्च का भुगतान कोयला घोटाले से जुड़ी राशि से किया गया था। ईओडब्ल्यू ने इस लेनदेन से

संबंधित जानकारी कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव और कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के बीच हुई चैट के आधार पर चार्जशीट में शामिल की है। दरअसल खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान कवि कुमार विश्वास का 'हमर भांचा राम' कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तब इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की थी। दावा किया गया था कि शासन रामनवमी पर शोभायात्रा निकालने नहीं दे रहा, जबकि कांग्रेस की ओर से आयोजित कुमार विश्वास के कार्यक्रम को अनुमति दी गई है। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के पेज नंबर 66 में कवि कुमार विश्वास को 25 लाख रुपये दिए जाने का उल्लेख किया गया है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में कवि सम्मेलन में शामिल अन्य कवियों को किए गए भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त का छत्तीसगढ़ दौरा स्थगित

रायपुर, 06 अक्टूबर 2026। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का छत्तीसगढ़ दौरा स्थगित हो गया है। उन्हें 7 और 8 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आना था। उनके दौर को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन ने प्रोटोकॉल की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। अब निर्वाचन आयोग की ओर से नई तारीख मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने लेटर संबंधित विभागों को भेजकर दौरा स्थगित होने की जानकारी दी है। पत्र में बताया गया है कि आयोग ने अपरिहार्य कारणों से मुख्य निर्वाचन आयुक्त का छत्तीसगढ़ प्रवास स्थगित किया है।



राज्य अतिथि के तौर पर होनी थी व्यवस्था

ज्ञानेश कुमार के दौर के दौरान उन्हें राज्य अतिथि घोषित किया गया था। उनके लिए जरूरी प्रोटोकॉल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत रायपुर कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के निदेशक, सुरक्षा अधिकारी, सीआईएसएफ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी सूचना भेजी गई थी।

बाद में मिलेगी नई तारीख की जानकारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने पत्र में कहा है कि, संशोधित कार्यक्रम की तारीख की जानकारी निर्वाचन आयोग से मिलने के बाद अलग से दी जाएगी। यानी फिलहाल ज्ञानेश कुमार के छत्तीसगढ़ आने की नई तारीख तय नहीं हुई है।

दूसरे लड़कों से बातचीत का शक... दोस्त से एसिड अटैक करवाया चेहरा-आंख झुलसे, कोचिंग में साथ पढ़ते थे, भीड़ ने आरोपियों को पीटा, फांसी की मांग

बालोद, 06 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बालोद में युवक ने हेड कॉन्स्टेबल की बेटी पर दोस्त से एसिड अटैक करवाया। 22 साल की छात्रा आमापारा की लाइब्रेरी से पढ़कर घर लौट रही थी, तभी आमापारा आत्मानंद स्कूल के सामने सिंचाई कॉलोनी में उस पर एसिड फेंका गया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी यश सोनकर और उसके दोस्त करण कुंजाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी बालोद का रहने वाला है और छात्रा के साथ कोचिंग में पढ़ चुका है। पिछले एक-डेढ़ साल से दोनों के बीच अफेयर था। युवक छात्रा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे शक था कि छात्रा दूसरे लड़कों से भी बात करने लगी है। इससे नाराज होकर उसने अपने बचपन के दोस्त से हमला करवाने की साजिश रची। हमले में छात्रा के शरीर का दाहिना हिस्सा, चेहरा और आंख के आसपास का हिस्सा बुरी तरह झुलस गया है। मंगलवार शाम करीब 5 बजे दोनों आरोपियों को बालोद कोर्ट में पेश



आरोपी भी पुलिसकर्मी का बेटा, अटैक से पहले शादी

मुख्य आरोपी बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम नेवारीखुर्द का रहने वाला है और बालोद शहर के आमापारा में किए गए मकान में रहता था। उसके पिता मानपुर-मोहला जिले में पदस्थ पुलिसकर्मी हैं। मुख्य आरोपी ने करीब एक सप्ताह पहले भैरमगढ़ (बीजापुर) से अपने बचपन के दोस्त को बालोद बुलाया था। दोस्त अपनी महिला मित्र को भी साथ लेकर आया था। पुलिस के अनुसार, सोमवार को एसिड अटैक से पहले आरोपी ने कमरोद में महिला मित्र की मांग भरकर उससे कथित रूप से शादी की थी। इसके बाद लाइब्रेरी से लौट रही छात्रा पर एसिड अटैक किया गया। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी को लगा था कि बाहर से बुलाया गया युवक वास्तव में बाद आसानी से निकल जाएगा और पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे कांडगांव से गिरफ्तार कर लिया।

करने के लिए ले जाया गया। पटेल मैदान के सामने भीड़ ने पुलिस वाहन रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया तो स्थिति बिगड़ गई।

उस भीड़ ने आरोपियों पर काला-नीला रंग फेंका और उन्हें जुते की माला पहनाने की कोशिश की। इस दौरान कई छात्राओं ने आरोपियों को झुलस गया। इसके बाद 5 अक्टूबर को उसने छात्रा पर हमला किया।



कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत का छत्तीसगढ़ दौरा

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत छत्तीसगढ़ दौर को लेकर दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के सुखदेव भगत रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर से सुबह 10 बजे बस्तर रवाना होंगे। कांकेर जिला मुख्यालय में 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैली में शामिल होंगे। दूतेशबाड़ में मां दत्तेश्वरी के दर्शन करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। जगदलपुर में भी बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत का तीन दिन का दौरा तय है।

अजय चंद्राकर के तंज पर बैज का पलटवार

सुखदेव भगत के दौर को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के तंज पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है। अजय चंद्राकर बताए कि छत्तीसगढ़ में सरकार की क्या हालत है। छत्तीसगढ़ क्या सुरक्षित है? हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। सभी मंत्री विभागों में लुट का काम कर रहे हैं।

विभाग छोड़ देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है।

क्षेत्रीय दलों की सक्रियता पर दीपक बैज का बयान : छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीतिक सक्रियता व चीफ को

लेकर दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और सभी राजनीतिक दल अपने एजेंडे से काम कर रहे हैं।

कोल घोटाले की अनुरूप चार्जशीट पर साधा निशाना : कोल घोटाले में अनुरूप चार्जशीट पेश होने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कोल घोटाला हो, शराब घोटाला हो या महदेव सट्टा घोटाला, इसमें केवल चार्जशीट की कार्रवाई चल रही है। सभी एजेंसियां जांच कर रही हैं। एनआईए भी इन मामलों में जांच कर सकती है।

बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग : निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग पर दीपक बैज ने कहा कि सभी चुनाव पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 निकायों में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। निकायों में आपसी विवाद को फैसला कर रही सियासत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस में कोई 'सिर फुटवेल' नहीं चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सगठन में 'सिर फुटवेल' चल रहा है। भाजपा केवल पचीं वाली पाटी है, तो वह प्रक्रिया नहीं जानते। चुनावी चंदा तो भाजपा का मामला है, इसलिए पंचतन पत्र साय को ट्रांसफर कर दिया गया। मंत्री केदार करयप से जुड़े जमीन मामले को लेकर दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि केदार करयप पहले 20 लाख की जमीन को 20 करोड़ में बेचने का फॉर्मूला बताएं।

गांव में पर्यटन बढ़ाने पर 1 लाख मिलेगा पुरस्कार... छत्तीसगढ़ में चेन्दरु राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार शुरू

रायपुर, 06 अक्टूबर 2026।

छत्तीसगढ़ के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने नया पुरस्कार शुरू किया है। 'चेन्दरु राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार' के तहत ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले व्यक्ति या संस्था को 1 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विजेता को राज्योत्सव के दौरान सम्मानित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए 'चेन्दरु राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार नियम, 2025' लागू किए हैं। पुरस्कार के जरिए गांवों की संस्कृति, परंपरा, खान-पान, हस्तशिल्प, लोककला और प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।



गांव में पर्यटक आएं तो स्थानीय लोगों की भी होगी कमाई : सरकार का फोकस केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि पर्यटन से होने वाली कमाई को गांवों तक पहुंचाने पर है। इसके लिए होमस्टे, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, लोककला और सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय युवा, महिलाएं, स्व-सहायता समूह, कारीगर और ग्रामीण उद्यमी पर्यटन से जुड़कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर हासिल कर सकेंगे।

पुरस्कार के लिए जारी होगा विज्ञापन : 'चेन्दरु राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार' के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर प्रविष्टियां आमंत्रित करेगा। आवेदन के साथ आवेदक को अपनी प्रोफाइल, फोटो, छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में किए गए काम और उपलब्धियों से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। पुरस्कार के लिए आने वाली प्रविष्टियों का मूल्यांकन 6 सदस्यीय निर्णायक मंडल करेगा। इसकी अध्यक्षता छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक करेंगे। जूरी में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। चयन में ग्रामीण पर्यटन के लिए किए गए काम के साथ उसके स्थानीय लोगों पर प्रभाव, रोजगार सृजन, समुदाय की भागीदारी और संस्कृति व प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण को भी देखा जाएगा।